अवहेलना : लोक शिक्षण आयुक्त के आदेश के बाद कलेक्टर ने भी लिखे पत्र

शिक्षकों को रास आ रहा बाबू का काम आदेश के बाद भी 300 नहीं लौटे पढ़ाने

प्रदेशभर में 12 हजार शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगे

वेतन रोकने के आदेश का भी नहीं किया गया पालन

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि

शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता काफी खराब है। हालात यह हैं कि प्रदेशभर में करीब 12 हजार शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हैं, जबकि अकेले ग्वालियर जिले में ही 200 से 300 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से विद्यालयों में छात्रों को नहीं पढ़ाया है। ऐसे शिक्षकों को वापस विद्यालयों में भेजने के लिए लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की आयुक्त जयश्री कियावत ने 21 जून 2019 को आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश के बाद भी अभी तक जिले के लगभग 300 शिक्षक वापस नहीं आए हैं। शिक्षकों को वापस भेजने के लिए विगत दिनों कलेक्टर अनुराग चौधरी ने भी पत्र जारी किया था, लेकिन यह पत्र भी बेअसर साबित हुआ।

शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर पदस्थ होने के बाद कुछ शिक्षकों ने जुगाड़ से अपना अटैचमेंट विभिन्न कार्यालयों में करा लिया है। ऐसे में शिक्षक वेतन तो शिक्षा विभाग से ले रहे हैं लेकिन कार्य दूसरे कार्यालयों में कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों के अटैचमेंट को समाप्त करने के कई बार आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यह शिक्षक वापस अपने पदों पर आना नहीं चाहते हैं। इसका कारण है मलाईदार पद का लालच। 21 जून 2019 को आयुक्त लोक शिक्षण ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया है कि गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजित समस्त शिक्षकों को उनकी मूल पाठशाला, विद्यालय में उपस्थित होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशित करें। अगर शिक्षक अपने मूल विद्यालय अथवा पाठशाला में उपस्थित नहीं होता है तो उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाए। साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखें कि निर्वाचन के नाम पर अथवा अन्य प्रयोजनों से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में रखे जाने पर आपके विरूद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस आदेश को जारी हुए साढ़े तीन माह बीत गए, लेकिन अभी तक धरातल पर हालत जस के तस बने हुए हैं।

एक-एक शिक्षक के भरोसे कई विद्यालय

जिलेभर में ऐसे कई विद्यालय हैं जो कि एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, इसके कारण यहां पर पढ़ने के लिए आने वाले शिक्षकों के भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग इस आदेश को हवा में उड़ाने में जुटा हुआ है।

इन विभागों में पदस्थ हैं शिक्षक : जिलेभर के लगभग 200 से 300 शिक्षक कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा, तहसील कार्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डीपीसी जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, जिला और जनपद पंचायतों में पदस्थ हैं।

सीधी बात

दीपक पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी

- **सवाल :** ग्वालियर में आदेश के बाद भी दो से तीन सैकड़ा शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं?
  जवाब : हां यह सही बात है। ग्वालियर में ऐसे कई शिक्षक हैं जो दूसरे विभागों में गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं।
- **सवाल :** शिक्षकों की अनुपस्थिति से क्या बच्चों की शिक्षा पर असर नहीं पड़ रहा?
  जवाब : छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। गणित, अंग्रेजी या विज्ञान विषय में शिक्षकों की अनुपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
- **सवाल :** इन्हें वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए?
  जवाब : शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किए गए। कलेक्टर साहब ने भी पत्र जारी किया, लेकिन शिक्षक लौटकर नहीं आए हैं।
- **सवाल :** स्कूलों में वापस न आने पर शिक्षकों की वेतन रोकने का आदेश दिया था, लेकिन 3 माह बीत गए अभी तक इसका पालन नहीं किया गया?
  जवाब : एक बार और पत्र जारी करते हैं। चूंकि अभी त्योहार चल रहे हैं, ऐसे में वेतन रोकना उचित नहीं होगा। पत्र के बाद शिक्षक नहीं लौटते हैं तो वेतन रोक दिया जाएगा।

दिवाली गिफ्ट : केंद्रीय कर्मियों का डीए 5% बढ़कर 17% हुआ

डीए में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा, सेंसेक्स 646 अंक उछला

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% करने को मंजूरी दे दी। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2019 से लागू होंगी। भत्ते की दरों में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह महंगाई भत्ते में एक बार में की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। कैबिनेट बैठक से पहले ही डीए बढ़ने की संभावनाओं के चलते शेयर बाजार में छह दिन से जारी गिरावट तो थमी ही, सेंसेक्स में इस साल की छठी सबसे बड़ी उछाल भी देखने को मिली। सेंसेक्स 646 अंक (1.72%) बढ़कर 38,178 पर बंद हुआ। यह इस साल की छठी सबसे बड़ी उछाल है। निफ्टी में 187 अंक (1.68%) की बढ़त रही। यह 11,313.30 पर बंद हुआ। छह दिन से सेंसेक्स 1,458 अंक और निफ्टी 445 अंक कमजोर हुआ था।

▪ लेकिन, रुपया 5 पैसे कमजोर हुआ

पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को एक डॉलर 71.02 रुपए का था, जो बुधवार को 71.07 रुपए का हो गया।

मप्र : राज्य कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला आकलन के बाद ही

भास्कर न्यूज. भोपाल | केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने का असर फिलहाल प्रदेश में नहीं होगा। राज्य सरकार पहले वित्तीय स्थिति का आकलन करेगी, उसके बाद ही राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर फैसला लेगी, क्योंकि 5 फीसदी डीए बढ़ाने से सरकार पर करीब 2745 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार आएगा। प्रदेश में बाढ़ से 16 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए अतिवृष्टि के नुकसान की भरपाई सरकार की प्राथमिकता में है।

डीए का गणित : अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा था। 4.50 लाख शासकीय सेवक, 2.25 लाख अध्यापक, 25 हजार पंचायत सचिवों को और 4.50 लाख पेंशनर्स को 1% डीए देने पर हर महीने 45.75 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्च आता है। शेष | पेज 9 पर

सेंसेक्स: साल की छठी बड़ी उछाल, 6 दिन से जारी गिरावट थमी

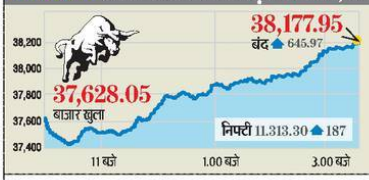

बैंकिंग शेयरों में मजबूती और महंगाई भत्ते की घोषणा से सुधरा बाजार

▪ सेंसेक्स में सुधार निजी बैंकों और वित्तीय शेयरों में मजबूती की वजह से आया। इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 5.45% की बढ़त दिखी। टेलीकॉम इंडेक्स में 4.92% की बढ़ोतरी रही।

पीओके से आए 5300 विस्थापित परिवारों को 5.5-5.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा

सरकार ने पीओके से विस्थापित 5300 परिवारों के पुनर्वास के लिए 5.5-5.5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। पीओके से आने के बाद यह परिवार शुरू में जम्मू-कश्मीर से बाहर जाकर बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य में लौट आए थे। सरकार ने 2016 में इनके लिए पैकेज घोषित किया था। 36,384 परिवारों को यह मुआवजा मिल चुका है।